डॉ. एस. मुरलीधर और अवनीश जिंगन, न्यायाधीश *के समक्ष*

विनोद कुमार- *याचिकाकर्ता*

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार के माध्यम से और अन्य - *प्रतिवादी*

2020 की सीडब्ल्यूपी संख्या 8343

नवम्बर 10/2020

पीएचडी में प्रवेश - अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण - सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार पर कब विचार किया जा सकता है?- 3 सीटों में से, हरियाणा ओपन जनरल श्रेणी (एचओजीसी) के लिए 1 और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 2 आरक्षित - छात्र अनिल मार्ले ने उच्चतम अंक (141.40) प्राप्त किए और ओबीसी श्रेणी के खिलाफ चुने गए- एचओजीसी के खिलाफ चुने गए दूसरे उम्मीदवार ने 137.10 अंक हासिल किए- तीसरे उम्मीदवार को 108.78 हासिल करते हुए ओबीसी कोटे में दिखाया गया था- याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अनिल मार्ले को एचओजीसी के विरुद्ध माना जाना चाहिए न कि ओबीसी कोटे के विरुद्ध क्योंकि उन्होंने एचओजीसी कोटे के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थी की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं - और अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में दूसरे उच्चतम अंक प्राप्त करने वाला याचिकाकर्ता प्रवेश प्राप्त करने में सक्षम होगा - प्रतिवादी विश्वविद्यालय ने सूचित किया कि अनिल मारले ने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए क्योंकि उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण होने वाले ओबीसी श्रेणी के अंतर्गत 15 अंकों का वेटेज दिया गया था। स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार, जो दी गई कुछ छूट के कारण कटौती करता है, को अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं माना जा सकता है - परिणामस्वरूप, सामान्य श्रेणी कोटा/रिक्तियों के विरुद्ध उस पर विचार नहीं किया जा सकता है - याचिका खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि ऊपर उल्लिखित स्थिति से जो परिणाम निकलता है, वह यह है कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उन्हें दी गई कुछ छूट के कारण कटौती करते हैं, तो जाहिर है, उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर योग्य नहीं माना जा सकता है और जिस स्थिति में उन्हें सामान्य श्रेणी के कोटे के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। इस कानूनी स्थिति को दीपा ईवी में दोनों में

समझाया गया है ***।*** *(सुप्रा) और* प्रदीप कुमार ***(सुप्रा)*** *में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में* सुप्रीम कोर्ट के अंतिम उल्लेखित फैसले में, यह नोट किया गया था कि उस मामले में प्रतिवादी केवल इसलिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने ओबीसी उम्मीदवारों के रूप में छूट का लाभ उठाया था और इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने "उन्हें सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र मानने पर विचार करना उचित नहीं समझा"।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता के वकीलराजेश तुषार।

प्रतीक महाजन, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के वकील।

डॉ. एस. मुरलीधर, न्यायाधीश

(एक) याचिकाकर्ता की शिकायत प्रतिवादी नंबर 1 विश्वविद्यालय में पीएचडी (लोक प्रशासन) कार्यक्रम में प्रवेश नहीं पाने के बारे में है, जिसके लिए उसने ओबीसी उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था। उन्होंने चयन प्रक्रिया में 103.26 अंक हासिल किए।

(दो) ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर तीन सीटें थीं। एक हरियाणा ओपन सामान्य श्रेणी ('एचओजीसी') के लिए और दो ओबीसी श्रेणी के लिए आरक्षित हैं। तीन चयनित उम्मीदवारों के संबंध में प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा जारी मेरिट सूची में, 141.40 के उच्चतम अंक हासिल करने वाले व्यक्ति यानी अनिल मालरे (प्रतिवादी नंबर 5) को ओबीसी श्रेणी में चयनित दिखाया गया था। दूसरा उम्मीदवार मि. 137.10 अंक हासिल करने वाले जसविंदर सिंह को एचओजीसी श्रेणी में दिखाया गया है। 108.78 अंक पाने वाले तीसरे अभ्यर्थी को ओबीसी वर्ग में दिखाया गया था।

(तीन) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि चूंकि श्री मालरे ने 141.40 अंक हासिल किए थे, जो एचओजीसी कोटे में चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों से अधिक था, श्री मालरे को एचओजीसी कोटा के खिलाफ माना जाना चाहिए न कि ओबीसी कोटे के खिलाफ। यदि उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया जाता है, तो याचिकाकर्ता, ओबीसी श्रेणी में दूसरा उच्चतम अंक प्राप्त करने के बाद, स्पष्ट रूप से कटौती करने में सक्षम होगा।

(चार) छोटा सवाल यह उठता है कि क्या श्री मालरे को श्री जसविंदर सिंह के स्थान पर एचओजीसी कोटा के तहत माना जाना चाहिए, जिससे याचिकाकर्ता को ओबीसी कोटा के तहत पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश सुरक्षित

करने का रास्ता मिल सके?

(पाँच) रितेश आर. साह ***बनाम*** *डॉ. वाई. एल. यमुल* ***और*** [1]समिता आंदोलन समिति ***बनाम*** *भारत संघ में* ***सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए*** [2]याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राजेश तुषार द्वारा यह तर्क दिया गया है कि श्री मालरे को एचओजीसी कोटा के खिलाफ माना जाना चाहिए।

(छः) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 और 2/विश्वविद्यालय के लिए उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रतीक महाजन द्वारा यह बताया गया है कि श्री मालरे ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) में अर्हता प्राप्त की है, जिसे ओबीसी श्रेणी के तहत 15 अंकों का वेटेज दिया गया था। उन्होंने श्री मालरे को जारी किए गए नेट प्रमाण पत्र की एक प्रति का उल्लेख किया है, जो प्रतिवादी नंबर 1 के उत्तर के साथ अनुलग्नक-आर 5 के रूप में संलग्न है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि श्री मालरे ने नेट में "ओबीसी श्रेणी के लिए योग्यता कट-ऑफ के बराबर अंक हासिल किए हैं"। दूसरे शब्दों में, उत्तरदाताओं का रुख यह है कि श्री मालरे को प्राप्त 15 अंकों का वेटेज केवल इसलिए था क्योंकि उन्हें ओबीसी श्रेणी के लिए लागू एक शिथिल मानक के संदर्भ में नेट में योग्य माना गया था।

(सात) श्री प्रतीक महाजन ने भी दीपा ईवी बनाम भारत ***संघ मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया*** *है।(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत* ***सरकार और*** [3]राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार बनाम *प्रदीप कुमार के विरुद्ध यह* ***तर्क देने के लिए कि चूंकि श्री मालरे अपनी योग्यता के आधार पर अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें एचओजीसी श्रेणी के विरुद्ध नहीं माना जा सकता।***[4]

(आठ) सामान्य श्रेणी के कोटे के खिलाफ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार पर विचार करने के संबंध में कानूनी स्थिति काफी अच्छी तरह से तय है। ***समता आंदोलन समिति*** (सुप्रा) **के हालिया फैसले में,** सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों को संक्षेप में प्रस्तुत करने के बाद कानूनी स्थिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया:

> "15. अब यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित श्रेणी के वे सदस्य जो अपनी योग्यता के आधार पर खुली

---

[1]एआईआर 1996 एससी 1378

[2](2014) 14 एससीसी 745

[3](2017) 12 एससीसी 680

[4](2019) 10 एससीसी 120

प्रतियोगिता में चुने जाते हैं, उन्हें सामान्य सूची/अनारक्षित श्रेणी में शामिल होने का अधिकार है और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटे के तहत नहीं गिना जाना चाहिए। (महत्त्व सन्निविष्ट)

(नौ) ऊपर उल्लिखित स्थिति से जो परिणाम उभरता है वह यह है कि यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार उन्हें दी गई कुछ छूट के कारण कटौती करते हैं, तो जाहिर है, उन्हें अपनी योग्यता के आधार पर योग्य नहीं माना जा सकता है और इस मामले में उन्हें सामान्य श्रेणी के कोटे के खिलाफ नहीं माना जा सकता है। इस कानूनी स्थिति को दीपा ईवी में दोनों में समझाया गया है ***(सुप्रा) और*** प्रदीप कुमार (सुप्रा) ***में सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले में*** सुप्रीम कोर्ट के अंतिम उल्लेखित फैसले में, यह नोट किया गया था कि उस मामले में प्रतिवादी केवल इसलिए अर्हता प्राप्त करने में सक्षम थे क्योंकि उन्होंने ओबीसी उम्मीदवारों के रूप में छूट का लाभ उठाया था और इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने "उन्हें सामान्य श्रेणी की रिक्तियों के लिए पात्र मानने पर विचार करना उचित नहीं समझा"।

(दस) यद्यपि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री राजेश तुषार ने एक योग्यता परीक्षा के आधार पर एक उम्मीदवार को अंक देने में एक शिथिल मानक और वेटेज के बीच अंतर करने की मांग की, जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, नेट में उत्तीर्ण होने वालों को दिए गए 15 अंकों का वेटेज श्री मालरे को नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उपलब्ध था। उन्होंने ओबीसी श्रेणी के तहत नेट के लिए उपस्थित होने वालों के लिए लागू मानक में ढील के कारण ऐसा किया। इस मामले के मद्देनजर, श्री मालरे को 'अपनी योग्यता के आधार पर' एचओजीसी कोटा के खिलाफ नहीं माना जा सकता है और ओबीसी कोटा के खिलाफ सही माना गया है।

(ग्यारह) तदनुसार, वर्तमान याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

त्रिभुवन ढैया

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाघला

प्रशिक्षु न्यायिकअधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

अंबाला,हरियाणा